PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 289 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | मंगलवार, 05 मई, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

पांच राज्यों के नतीजों ने बदली देश की राजनीति की दिशा

कमल का बंगाल विजयगर्जन

जनता ने बदला जनादेश, भाजपा को स्पष्ट बहुमत

केरलम में कांग्रेस का कमबैक

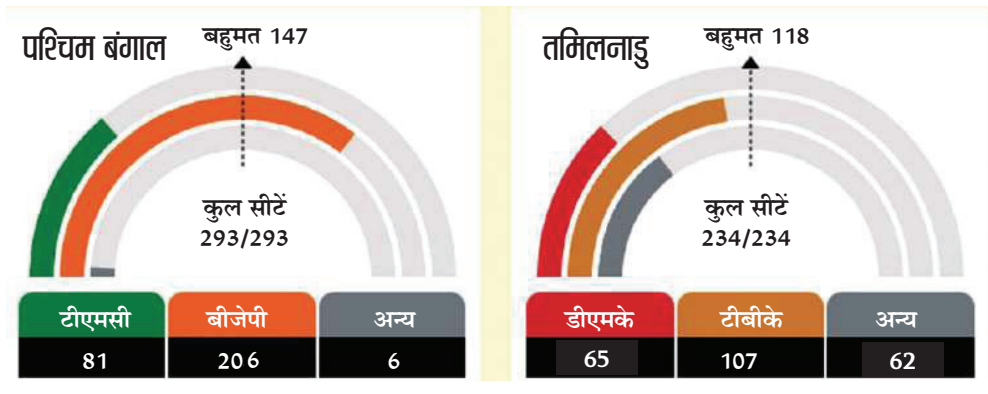

पुडुचेरी में एनडीए की सरकार, असम में हिमंता नहीं हिले

तमिलनाडु में विजय 'सुपरस्टार'

लोक टुडे। जयपुर

देश के पांच राज्यों में सोमवार को आए विधानसभा चुनावों के परिणाम ने सभी को चौंका दिया है। खासकर पच्छिम बंगाल में देर रात तक राजनीतिक तस्वीर साफ हुई। विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाया है तो असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड जीत हासिल की। राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी हो रही है, जिसे पार्टी की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और राज्य सरकार के कामकाज का परिणाम बताया जा रहा है। तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अभिनेता थलापति विजय की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई है। वहीं केरल में लेफ्ट का किला ढह गया और राज्य में कांग्रेस-नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत हुई है। इसके अलावा पुडुचेरी में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।

पश्चिम बंगाल - ममता दीदी की व्यक्तिगत हार के साथ सत्ता से विदाई :

बीजेपी ने 293 सीटों में से 206 से जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस लगभग 81 सीटों पर सिमटी है। राज्य में इस बार लगभग 92.93% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो बंगाल के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक है।

हार और जीत के बड़े कारण :

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी मशीनरी के प्रति लोगों की नाराजगी और बदलाव की इच्छा ने बीजेपी को जीत दिलाई। बीजेपी ने मुस्लिम, महिला, प्रवासी, मतुआ समुदाय और अपनी मजबूत चुनावी मशीनरी के जरिए ममता के गढ़ में सेंध लगाई। बीजेपी ने प्रेसीडेंसी और दक्षिण बंगाल जैसे टीएमसी के मजबूत इलाकों में भी बड़ी जीत हासिल की है।

झालमुड़ी बना इंटरनेशनल ब्रांड :

वैसे तो झालमुड़ी सभी के घर में बनती है। कभी कभी नाश्ते में या बच्चों को हलका खाने के हिसाब से खिला दी जाती है। लेकिन इन दिनों झालमुड़ी नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। दरअसल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में दौरे के दौरान एक दुकान से झालमुड़ी खरीदकर खाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेड हुआ। सियासत में भी इसका खूब जिक्र हुआ और झालमुड़ी का झटका इतना जोर का लगा कि बंगाल से टीएमसी को भारी नुकसान हुआ। अब लोग झालमुड़ी को सर्च भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं।

तमिलनाडू — अभिनेता थलापति का 'विजय' घोष :

एक्टर थलापति विजय की तमिलनाडू में भी एंट्री हीरो की तरह रही। वर्ष 2024 में राजनीतिक पार्टी बनाकर सबको चौकाने वाले को मौजूदा सरकार डीएमके ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उनकी चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर बीजेपी ने जरुर गठबंधन की कोशिश की। लेकिन विजय थलापति अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और स्वामी पेरियार एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र में पुरा भरोसा करते हुए अपने दम पर लड़े। नतीजा सबके सामने है, आज तमिलनाडू में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और विजय भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी।

कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए गठबंधन का न्यौता :

तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन वे बहुमत के आंकड़े से दूर रह गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय के पिता ने कांग्रेस को गठबंधन का न्यौता दिया है, ताकि मिलकर सरकार बनाई जा सके।

असम — हिमंता बिस्व सरमा की पॉपुलैरिटी कायम

यहाँ भी बीजेपी ने तीन-चौथाई बहुमत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखी है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन काफी पीछे रह गया है। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक नई सीमाओं ने मुस्लिम बहुल इलाकों के प्रभाव को सीमित कर दिया। साथ ही उन सीटों को भी फिर से व्यवस्थित किया जहां असमिया मुसलमान कम हो रहे थे। इससे हिमंत को उन सीटों पर बढ़त मिली जहां पहले भाजपा कमजोर थी। 2021 में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने साथ चुनाव लड़ा था। उन्हें बंगाली मुसलमानों के 89% तो असमी मुसलमानों के 65% वोट मिले थे। 2026 में यह दोनों धड़े अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रैटजी साफ थी कि मुस्लिम वोट बांटकर विपक्ष को होने वाले फायदे को घटाया जाए। बीजेपी ने असम के मूल मुसलमानों को भी अपने पाले में करने की कोशिश की। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक, 'हिमंता मुस्लिम समुदाय के भीतर दो गुट पैदा करने में सफल रहे हैं। पहले उन्होंने बांग्लादेश से आए 'मियां मुसलमानों' को असमी मुसलमानों के लिए खतरा बताया। फिर असमी मुसलमानों को विशेष दर्जा देकर, उन्हें अपने पाले में सुरक्षित कर लिया। हिमंता बिस्वा सरमा की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ वोट में कन्वर्ट हो गई। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इससे असमी संस्कृति, परंपरा और भाषा को खतरा बताया। उन्होंने दावा किया कि हर हफ्ते 35-40 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज रहे हैं। इससे हिंदू वोटों में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती चली गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अदिप फुकन के मुताबिक असम में पहली बार पूरा चुनाव हिमंता के चेहरे पर लड़ा गया। वे अपने तीखे बयानों से खुद को योगी जैसे कट्टर नेता के तौर पर स्थापित करने में सफल हुए।

केरलम — फिर से केरलम बना कांग्रेस गढ़ :

केरलम ही केवल कांग्रेस की खुशी की वजह बनी। केरलम में 1977 से 2016 तक हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2021 में यह ट्रेंड बदला और लगातार दो बार लेफ्ट की सरकार बनी। लेकिन 10 साल एक ही सरकार रहने के बाद ट्रेंड फिर वापस आ गया। इसकी झलक पहले लोकसभा इलेक्शन में दिखी, जहां UDF ने 18 और LDF ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। फिर दिसंबर 2025 के लोकल बॉडी इलेक्शन में भी UDF को 38.81% वोट के साथ बढ़त मिली। LDF को 33.45% वोट मिले। LDF ने 81 साल के हो चुके पिनरई विजयन के नाम पर ही चुनाव लड़ा, जिससे यह मैसेज भी गया कि लेफ्ट के पास विजयन के अलावा और कोई चेहरा नहीं है।

ट्रेंड कांग्रेस की जीत की चाबी बना :

कई सर्वे बता रहे हैं कि इस बार माइनॉरिटी एकजुट होकर UDF को वोट किया है। पिछले इलेक्शन में यही वोट LDF को मिला था, जिससे UDF कमजोर पड़ गई थी। केरलम के सीएम पिनरई विजयन के परिवार पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें CPI(M) नेता ए. पद्मकुमार भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में यह मुद्दा उठाकर कहा था कि जो सरकार भगवान अयप्पा का सम्मान नहीं कर सकती, केरलम के लोगों का सम्मान क्या करेगी?

भाजपा की जीत पर जश्न, मुख्यालय पर आतिशबाजी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में मिली जीत के बाद पार्टी मुख्यालयों पर जश्न का माहौल देखने को मिला। खासकर पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में बेहतर प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह रहा। जीत की खुशी में कई स्थानों पर आतिशबाजी की गई। ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और भारत माता की जय व पार्टी के पक्ष में नारे लगाए गए। राजस्थान में भी भाजपा मुख्यालय पर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया सहित कई बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेताओं का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक अंदाज में झालमुड़ी खाते हुए नेताओं की तस्वीरें भी चर्चा में रहीं, जिसने माहौल को और भी सहज और उत्सवपूर्ण बना दिया। जश्न के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ अपनी खुशी जाहिर की।

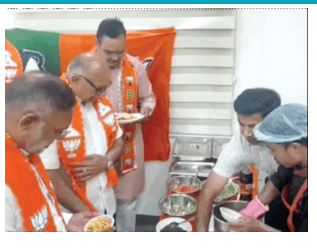

सम्पादकीय

बरगी बांध हादसा

रोमांच बना मौत का सफर, क्या सिर्फ प्रतिबंध से खत्म होगी लापरवाही

मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज नाव के पलटने से हुए हादसे की त्रासदी ने एक बार फिर नागरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे ने नाव पर सवार होकर रोमांच महसूस करने के कई लोगों के उत्साह को मातम में बदल दिया। हैरानी इस बात की है कि दुर्घटना के बाद प्रशासन के पास नाव में सवार कुल लोगों की सटीक जानकारी तक नहीं थी। अधिकारियों ने टिकटों की संख्या के आधार पर आंकड़ा जारी कर दिया, जबकि कई लोगों के साथ उनके बच्चे भी नाव पर सवार थे।

सवाल है कि नौकाओं के संचालकों के लिए क्या यह नियम जरूरी नहीं होना चाहिए कि टिकट लेने वाले लोगों के साथ उनके बच्चों की संख्या भी दर्ज की जाए, ताकि आपात स्थिति में सुरक्षा बंदोबस्त में कोई कमी न रहे? दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आई हैं कि दुर्घटना की शिकार हुई नौका पर पहले से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और न ही स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान की कोई व्यवस्था थी। ऐसे में इसे व्यवस्थागत लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा।

गौरतलब है कि गुरुवार को बरगी बांध में एक क्रूज नौका तेज आंधी की चपेट में आकर पलट गई थी। इस दुर्घटना में अब तक नौ लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि कुछ लोग अब भी लापता हैं। हादसे में जीवित बचे लोगों का दावा है कि नौका पर सवार किसी भी यात्री ने जीवन रक्षक जैकेट नहीं पहनी थी। जब आपात स्थिति महसूस हुई, तभी वे यात्रियों में वितरित करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों को इन्हें पहनने का मौका ही नहीं मिला। सवाल है कि जो नियम नौका चालकों को प्रशिक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से सिखाए जाते हैं, अगर उन्हें ही नजरअंदाज कर दिया जाए, तो यह सीधे तौर पर लापरवाही को उजागर करता है। यही नहीं, जल पर्यटन के इस क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान की व्यवस्था न होना भी सवाल खड़े करती है। राज्य सरकार ने हादसे के बाद क्रूज नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन क्या सिर्फ इस कदम से ऐसी दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक पाएगी। ऐसे में सभी राज्यों को चाहिए कि इस हादसे से सबक लेकर तमाम व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए।

वैश्विक संकट बना अमेरिका-ईरान का टकराव

होर्मुज समुद्री मार्ग पर ईरान के आधिपत्य जमाने की कोशिश और इसके जवाब में अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते पूरे विश्व में ऊर्जा का न केवल संकट बरकरार है, बल्कि वह गहराता भी जा रहा है। जहां अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों को नहीं निकलने दे रहा है, वहीं ईरान होर्मुज से तेल और गैस लेकर आ रहे जहाजों को रास्ता नहीं दे रहा है। एक तरह से दोनों देश अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। यह तब है, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम भी कायम है। फिलहाल इस युद्धविराम से दुनिया को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट यथावत है और होर्मुज पहले की तरह बाधित है। ट्रंप ने युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के बाद जब ईरान पर परमाणु मसले पर जल्द समझौते के लिए दबाव डालना शुरू किया तो प्रारंभ में तो वह इस दबाव का प्रतिकार करते दिखा, लेकिन अपने बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी से वह अब कुछ बेचैन दिख रहा है। इसका कारण यह है कि वह जिस तेल का उत्पादन कर रहा है, उसका निर्यात नहीं कर पा रहा है और उसके पास अब और अधिक तेल के भंडारण की क्षमता नहीं बची। ऐसे में उसे अपने तेल कुओं को बंद करना पड़ सकता है। इसके नतीजे में उन्हें स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। शायद इसी कारण ईरान ने पाकिस्तान के जरिये अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन वह ट्रंप को रास नहीं आया। देखना है कि इसके बाद ईरान क्या करता है और ट्रंप क्या करते हैं? यदि ईरान परमाणु मसले पर समझौते से इन्कार करता रहता है तो ट्रंप उसे नए सिरे से निशाना बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट को लेकर वे अपने घर में ही आलोचना से घिर गए हैं। उनके रक्षा मंत्री विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों को यह बता पाने में नाकाम हैं कि ईरान के खिलाफ चले 40 दिन के युद्ध में अमेरिका को क्या हासिल हुआ? अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता विफल होने और दूसरे दौर की वार्ता कराने में पाकिस्तान के नाकाम हो जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकट सुलझाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, लेकिन इससे भी बात बनती नहीं दिखी। इस बातचीत में रूस ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर बात तभी आगे बढ़ सकेगी, जब ईरान सहमत होगा।

आज यक्ष प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम कायम रहेगा या नहीं, बल्कि यह है कि होर्मुज समुद्री मार्ग खुलेगा या नहीं? यदि यह समुद्री मार्ग नहीं खुलता तो तेल और गैस के दाम नीचे आने वाले नहीं और यदि वे इसी तरह बढ़ते रहे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। कई देशों में तो तेल और गैस के दाम बढ़ भी गए हैं। इसका प्रतिकूल असर उद्योग-धंधों के साथ रोजगार पर भी पड़ रहा है। अभी तक भारत को केवल एलपीजी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस किल्लत के बीच कमर्शियल सिलिंडरों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पिछले कुछ समय से कारखानों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कमी भी देखी जा रही है और उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कहीं-कहीं श्रमिकों के काम के घंटों और दिनों में भी कटौती होने लगी है। एक समस्या यह भी है कि निर्यातक अपना सामान खाड़ी के देश नहीं भेज पा रहे हैं। इसी तरह खाड़ी देशों से तेल और गैस के अलावा अन्य उत्पाद भी नहीं आ पा रहे हैं। इसका भी असर उद्योगों पर पड़ रहा है।

जहां तेल के दाम 125 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गए हैं, वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को लांघ गया है। यह भारत के लिए दोहरा संकट है, क्योंकि इससे आयात बिल बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों और रुपये में गिरावट से महंगाई बढ़ने का खतरा है। अब तो इसकी भी आशंका है कि तेल कंपनियों को अपना घाटा कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो महंगाई का तेजी से बढ़ना तय है। महंगाई बढ़ने से आम आदमी के समक्ष संकट तो बढ़ेगा ही, सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सरकार कुछ भी दावा करे, उसके लिए बहुत दिनों तक पेट्रोल और डीजल के मूल्य स्थिर रखना कठिन होगा। यह ध्यान रहे कि कच्चे तेल के बढ़े दामों के बोझ से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार पहले ही अपने टैक्स राजस्व में कटौती कर चुकी है।

इसके तहत पिछले माह पेट्रोल और डीजल, दोनों पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई थी, लेकिन आगे उसके लिए ऐसा करना कठिन होगा। सरकार ने अभी तक भले ही पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे हों, लेकिन उसे कमर्शियल सिलिंडर के दाम बढ़ाने के साथ विदेशी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम बढ़ाने पड़े हैं। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा मंहगी हुई। गत दिवस फिर से एटीएफ के मूल्य बढ़ाए गए। इससे अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा और महंगी होना तय है। कुछ एयरलाइंस की घरेलू यात्रा भी महंगी हो गई है। स्पष्ट है इसका असर आम लोगों के साथ आर्थिकी पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल गैस की ही किल्लत देखने को मिल रही है। चूंकि उर्वरक उत्पादन में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, इसलिए उसके भी दाम बढ़ने और उसकी आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। तारकोल भी पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक उप-उत्पाद है और देश में उसकी भी कमी देखी जा रही है।

यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी रहती है और होर्मुज समुद्री मार्ग नहीं खुलता तो पश्चिम एशिया का संकट पूरी दुनिया के लिए कहीं बड़े संकट में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए केवल अमेरिका और इजरायल ही नहीं, बल्कि ईरान भी दोषी होगा, क्योंकि अब वह भी हठधर्मिता दिखा रहा है। जहां अमेरिका चाह रहा है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्थगित करे, वहीं पहले इसी मसले पर अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात कर रहे ईरानी नेता अब यह कह रहे हैं कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि ईरान का यह रुख न तो अमेरिका को स्वीकार होगा, न इजरायल को और न ही खाड़ी देशों को।

शिक्षकों के बिना शिक्षा, करीब दस लाख पद खाली

का ह निराशाजनक है कि राज्यों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को फिर से चिंता जतानी पड़ी। इस समिति ने पिछले वर्ष भी स्कूली शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए उन्हें इस वर्ष मार्च तक भरने की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए अब इस समिति ने शिक्षकों के खाली पद भरने में देरी करने वाले राज्यों की वित्तीय मदद रोकने का सुझाव दिया है। समिति के अनुसार जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पद नहीं भरते, तब तक उन्हें समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद न दी जाए।

यदि ऐसा किया जाता है तो यह भी संभव है कि राज्य वित्तीय सहायता के अभाव में रिक्त शिक्षकों के पद भरने में और अधिक सुस्ती दिखाएं। यह ध्यान रहे कि संसदीय समिति की तरह से शिक्षा मंत्रालय भी राज्यों से शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का आग्रह कर चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। यह सामान्य बात नहीं कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षकों के करीब दस लाख पद खाली पड़े हैं। इनमें लगभग साढ़े सात लाख पद प्राथमिक शिक्षकों के है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर की जा रही है।

यह एक विडंबना ही है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में पिछले कई वर्षों से ढिलाई बरती जा रही है। यह ढिलाई यही बताती है कि राज्य सरकारें स्कूली शिक्षा की दशा-दिशा सुधारने के प्रति गंभीर नहीं। उनकी इस अगंभीरता का परिचय उन सर्वेक्षणों से मिलता है, जो प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा को रेखांकित करते रहते हैं। ये सर्वेक्षण यह बताते रहे हैं कि किस तरह चौथी-पांचवीं के छात्रों को सामान्य जोड़-घटाव करने में कठिनाई होती है या फिर वे दो-तीन वाक्य भी सही तरह नहीं लिख पाते।

यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद तो लें, पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने में आनाकानी करें। यह विचित्र है कि जो काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, वही एजेंडे से बाहर दिखता है। इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्यों में कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं।

ओपेक का बदलता वर्चस्व : संयुक्त अरब अमीरात की चुनौती और भारत के लिए नए अवसर

लेखक - कर्नल देव आनंद लोहमरोर (सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

ओपेक आधुनिक वैश्विक ऊर्जा भू-राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसने पिछले छह दशकों में तेल की कीमतों, आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इन तेल समृद्ध देशों ने पश्चिमी तेल कंपनियों, जिन्हें आमतौर पर 'सेवन सिस्टर्स' कहा जाता था, के वर्चस्व को चुनौती देने और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए हाथ मिलाया था। 'सेवन सिस्टर्स शब्द सात प्रमुख पश्चिमी तेल कंपनियों (एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी, रॉयल डच शेल, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यूयॉर्क, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑयल और टेक्सैको) को संदर्भित करता है। इन्होंने 1920 से 1960 के बीच वैश्विक तेल उत्पादन, मूल्य निर्धारण और निर्यात नीतियों पर नियंत्रण रखा था। विशाल तेल भंडार होने के बावजूद, उत्पादक देशों को सीमित लाभ मिलता था, जिससे असंतोष बढ़ा और अंततः तेल नीतियों पर अपना अधिकार फिर से हासिल करने के लिए ओपेक का गठन हुआ।

समय के साथ ओपेक का विस्तार हुआ और विभिन्न चरणों में नए देश इसमें शामिल हुए। कतर 1961 में शामिल हुआ (और 2019 में बाहर निकल गया), इंडोनेशिया और लीबिया 1962 में (इंडोनेशिया बाद में बाहर हो गया), और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 1967 में शामिल हुआ, जिससे खाड़ी देशों का प्रभाव और मजबूत हुआ। इसके बाद अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973, बाद में बाहर हो गया) और गैबॉन (1975, बाहर होकर फिर शामिल हुआ) इसके सदस्य बने। 21वीं सदी में अंगोला (2007, 2024 में बाहर), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018) के शामिल होने से ओपेक उतार-चढ़ाव वाली सदस्यता वाला एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा मंच बन गया। हालाँकि ओपेक का आधिकारिक लक्ष्य बाजार स्थिरता और उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह एक 'कार्टेल' (गुट) की तरह काम करता है, जहाँ सदस्य देश उत्पादन स्तरों का समन्वय करते हैं। इसके पीछे का तर्क सरल है। अनियंत्रित उत्पादन से बाजार में तेल की बाढ़ आ जाएगी, जिससे कीमतें गिरेंगी और उत्पादकों को नुकसान होगा। उत्पादन को नियंत्रित करके, ओपेक कीमतों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई है। 1973 के तेल संकट के दौरान, ओपेक ने पश्चिमी देशों के खिलाफ तेल आपूर्ति को एक भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, जिससे अर्थशास्त्र से परे इसके रणनीतिक प्रभाव का पता चला। 2000 के दशक के बाद से वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका में शेल तेल क्रांति और रूस द्वारा बढ़ते तेल उत्पादन ने ओपेक के पारंपरिक दबदबे को कमजोर कर दिया। इसके जवाब में, 2016 में 'ओपेक+' (OPEC+) का गठन किया गया, जिसमें ओपेक सदस्यों और रूस जैसे गैर-ओपेक उत्पादकों को उत्पादन समन्वय और बाजार स्थिरता के लिए साथ लाया गया।

इस बदलते ढांचे में, संयुक्त अरब अमीरात (1967 से सदस्य और 'स्पेयर कैपेसिटी' का प्रमुख धारक) ने अपनी बढ़ती क्षमताओं के कारण उत्पादन कोटा पर असंतोष व्यक्त किया है। इससे समूह के भीतर, विशेष रूप से सऊदी अरब के साथ रणनीतिक मतभेद पैदा हुए हैं। हालाँकि ओपेक सीधे तौर पर बिक्री को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन यह उत्पादन सीमाओं के माध्यम से बाजारों को प्रभावित करता है। यदि यूएई अधिक स्वतंत्र रुख अपनाता है, तब भी ओपेक का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा—जैसा कि 2019 में कतर और 2023/24 में अंगोला के बाहर निकलने पर देखा गया—लेकिन वैश्विक तेल बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी और बहुध्रुवीय हो जाएगा, जिससे भारत जैसे प्रमुख आयातकों को लाभ होगा। यह तर्क कि ओपेक वैश्विक कीमतों में हेरफेर करता है, पूरी तरह निराधार नहीं है, लेकिन यह पूरी तस्वीर भी नहीं है। जहाँ ओपेक आपूर्ति प्रबंधन के माध्यम से कीमतों को प्रभावित करता है, वहीं अब इसका विशेष नियंत्रण नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस भी वैश्विक तेल गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार, वास्तविकता नियंत्रण या जबरदस्ती की एक साधारण कहानी की तुलना में कहीं अधिक जटिल और बहुध्रुवीय है।

शोर का न ओर-छोर

यूं तो हाल के वर्षों में आम भारतीय की अभिव्यक्ति में तल्खी व शोर का ग्राफ तेज हुआ है। अभिव्यक्ति का मुखर होना अच्छा है लेकिन उसका तल्ख होना, किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे हमारे परिवेश में लगातार बढ़ता शोर झेलना हमारी नियति हो चला है। सड़कों पर वाहनों के शोर, नये दौर के कर्कश संगीत से लेकर राजनीतिक विमर्श में होने वाले शोरगुल वाले संवाद से लेकर तमाम ऐसा कुछ घट रहा है, जो हमारी परेशानी का सबब बन रहा है। यूं तो कोई प्रमाणिक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक शोध व्यापक रूप में हमारे सामने तो नहीं आए हैं जो ठीक-ठीक बताएं कि ध्वनि प्रदूषण हमारी सेहत पर कितना घातक असर डाल रहा है। लेकिन गाहे-बगाहे सामने आए आंकड़े इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि लगातार बढ़ता शोर हमारी सेहत बिगाड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने के लिए उचित निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और दंड के प्रावधान लागू होते नजर नहीं आते हैं। लेकिन विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष बता रहे हैं देश के महानगरों से लेकर कस्बों तक हमारे परिवेश का शोर तय मानकों से कहीं अधिक है। जाहिरा तौर ये शोर हमारी सेहत को गहरे तक प्रभावित कर रहा है। जिससे न केवल हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है बल्कि नींद में कमी, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप के अलावा हृदय रोग तक का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इस दिशा में कागजों में तो लुभावनी योजनाएं तो बनायी जाती हैं लेकिन जमीनी हकीकत बदलती नजर नहीं आती। यह सुखद है कि पिछले दिनों देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस दिशा में नई पहल शुरू की गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया आरंभ की है। दावा किया जा रहा है कि प्रदूषण के स्रोतों की कायदे से निगरानी होगी। इसके अलावा समयबद्ध ढंग से कार्रवाई होगी। साथ ही जुर्माना भी अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अच्छी योजना कितनी जमीनी हकीकत बनती है।

लेकिन सवाल यह है कि जब देश में पहले से शोर नियंत्रण के कानून मौजूद हैं और हमारी अदालतें भी समय-समय पर हमारे नीति नियंताओं को आगाह करती ही रहती हैं, तो फिर सूरत क्यों नहीं बदलती। आखिर इन नियम-कानूनों के क्रियान्वयन में कहां खोट रह जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम, 2000 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों, निर्माण कार्यों और उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों, वाहनों के हार्न आदि अन्य स्रोतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो पाए। उल्लेखनीय है कि ये प्रावधान दिन व रात के लिये अलग-अलग हैं।

विशेष आलेख /राशिफल

पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बने

भारत में बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन एक गहरी पारिस्थितिकीय समस्या को उजागर करते हैं, जो मानव-निर्मित हैं। विकास योजनाओं और पर्यावरणीय लापरवाही ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है।

भारत में मौसम का बदलता मिजाज और वैशाख के महीने में जेठ जैसी तपिश का अहसास होना अब केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरे पारिस्थितिक संकट की चेतावनी है। अक्सर भीषण गर्मी और लू के लिए अल नीनो या वैश्विक जलवायु परिवर्तन को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह संकट काफी हद तक मानव-निर्मित है।

आज हम जिस भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, वह वैश्विक वायुमंडलीय बदलावों और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति बरती गई नीतिगत लापरवाही का एक मिला-जुला परिणाम है। जब हम अपनी विकास योजनाओं के नाम पर हज़ारों हेक्टेयर प्राथमिक जंगलों, पहाड़ियों और जल निकायों को नष्ट करते हैं, तो हम अनजाने में उन प्राकृतिक 'कूलिंग एजेंटों' को खत्म कर देते हैं जो इस तपिश के खिलाफ हमारी एकमात्र सुरक्षा थे। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में, जहां तापमान अब नियमित रूप से 48 डिग्री सेल्सियस के स्तर को छूने लगा है, यह स्पष्ट है कि हमारी विकास की भूख ने धरती के प्राकृतिक थर्मोस्टेट को बिगाड़ दिया है।

इस मानव-निर्मित गर्मी की सबसे प्रत्यक्ष और क्रूर मार उन मजदूरों और सड़क किनारे काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ती है जो इस ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। भारत के करोड़ों निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और गिग-इकोनॉमी के कर्मचारी इस गर्मी को केवल एक आंकड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक शारीरिक हमले के रूप में महसूस करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, गर्मी के कारण भारत को 2030 तक अपने कुल कामकाजी घंटों का 5.8 प्रतिशत हिस्सा खोना पड़ सकता है, जो लगभग 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है। बांदा जैसे शहरों में, कंक्रीट और कोलतार की सड़कें गर्मी को सोखकर रात में भी उसे वापस छोड़ती हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव पैदा होता है और स्थानीय तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना रहता है। नीतिगत स्तर पर मजदूरों के लिए 'छाया का अधिकार' या लू के दौरान काम के घंटों में बदलाव जैसे नियम केवल कागजों तक सीमित हैं, जो हमारे विकास के उस अंधेपन को दर्शाते हैं जहां श्रम को एक जैविक इकाई के बजाय केवल एक मशीन समझा जाता है। गर्मी का यह घातक रूप हमारी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। 'थर्मल शॉक' के कारण गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के दाने दूध भरने की अवस्था में ही सूख रहे हैं, जिससे पैदावार में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। मिट्टी की नमी खत्म होने से उपजाऊ जमीन अब मरुस्थल में बदल रही है, फिर भी हमारी नीतियां सूखे क्षेत्रों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही हैं। इसी तरह, जंगलों के विखंडन और अवैध खनन ने वन्यजीवों के लिए भोजन का संकट पैदा कर दिया है। छतरपुर और पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में, खनन के कारण प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप जंगली जानवरों का बस्तियों की ओर आना 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह केवल मानव-पशु संघर्ष नहीं है, बल्कि उस पारिस्थितिक सुरक्षा चक्र का टूटना है जो इंसानों और जानवरों को एक साथ सुरक्षित रखता था।

वर्तमान 'हीट एक्शन प्लान' (एचएपी) की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वे केवल शहरों में मौतों को रोकने पर केंद्रित हैं, जबकि जमीन, जल और मिट्टी के गिरते स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। अब समय आ गया है कि नीतिगत स्तर पर 'वन हेल्थ' के दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जहां मिट्टी की नमी, पशुधन का स्वास्थ्य और वन्यजीवों का संरक्षण एक ही इकाई के रूप में देखा जाए। हमें केवल पौधारोपण की रस्म अदायगी से ऊपर उठकर बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाबों जैसे पारंपरिक जल-प्रबंधन तंत्र को पुनर्जीवित करना होगा। ये तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय पारिस्थितिकी को ठंडा रखने के विकेंद्रीकृत साधन थे। नीति-निर्माताओं को यह समझना होगा कि राजमार्गों के लिए काटे गए पेड़ केवल लकड़ी नहीं थे, बल्कि वे उस सूक्ष्म-जलवायु का हिस्सा थे जो फसलों को झुलसने से बचाती थी।

हमें विकास की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। बुंदेलखंड में पत्थर खनन के लिए काटी गई हर पहाड़ी और उत्तराखंड में कंक्रीट के विस्तार के लिए नष्ट की गई हरियाली हमारे भविष्य की ठंडी हवाओं को रोक रही है। आर्थिक लाभ की तुलना में गर्मी के कारण होने वाला स्वास्थ्य और कृषि का नुकसान कहीं अधिक है। भविष्य की नीतियों की सफलता अब इस जवाबदेही पर टिकी है कि हम बुनियादी ढांचे के निर्माण में 'ग्रीन इंजीनियरिंग' को कितनी प्राथमिकता देते हैं और पर्यावरण नियमों की अनदेखी को कब बंद करते हैं।

क्या कहते है आपके सितारें....?

मेष आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है। शारीरिक थकान और मानसिक तनाव अधिक रहेगा। मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है।

वृषभ नेगेटिव विचारों से मन परेशान रह सकता है। मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव नहीं करेंगे। निराशा और असंतोष की भावना से काम में मन नहीं लगेगा।

मिथुन आपको उग्र स्वभाव पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। आज आप मानसिकरूप से थकान का अनुभव करेंगे। अधिक परिश्रम की तुलना में कम फल की प्राप्ति होगी।

कर्क रोमांस के लिए आज अनुकूल दिन है। आज का हर कार्य आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे। प्रवास-पर्यटन की संभावनाएं है।

सिंह आपका आज का दिन शुभफलदायी है। इनकम में भी वृद्धि हो सकती है। मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी हो सकता है। पर्यटन स्थल की सैर आपको रोमांचित करेगी।

कन्या नई योजना का आरंभ करने के लिए आज अनुकूल दिन है। सरकारी काम में लाभ होगा। अधिकारियों से काम का उचित फल भी मिल सकता है। भाई-बंधुओं के साथ कोई झगड़ा दूर होगा।

तुला आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। आप का हर काम आज सफलता से पूरा होगा।

वृश्चिक आज अचानक धन खर्च होने का योग है। यह खर्च स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है। व्यावहारिक या सामाजिक काम के लिए बाहर जाना हो सकता है। खान-पान में ध्यान रखें।

धनु आप में आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप जल्दबाज़ी में निर्णय ले सकते हैं। पिता तथा बड़ों की ओर से लाभ होगा।

मकर आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। उसमें सफलता भी प्राप्त भी करेंगे। पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है।

कुंभ आज आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है। शारीरिक रूप से आलस्य और अशक्ति का अनुभव करेंगे। मन में चिंता रह सकती है। व्यापार में बाधाएं उपस्थित होंगी।

मीन आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपके मनोबल और आत्मविश्वास में दृढ़ता का अनुभव होगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा।

नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र

बिना बैंक से कर्ज लिए 4,200 करोड़ की गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना पूरीः सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी अपने वित्तीय संसाधनों से पूरा करने की क्षमता रखता है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे में शामिल करीब 600 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण बिना बैंकों से कर्ज लिए पूरा किया गया। इसमें 36,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। एक्सप्रेसवे के किनारे नौ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए करीब 7,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन ली गई है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर व लॉजिस्टिक हब को मिलाकर पूरी परियोजना पर 42,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2017 से पहले यह स्थिति नहीं थी, प्रदेश को 'बीमारू' माना जाता था। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान राज्य को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन, अब यूपी 'रेवेन्यू सरप्लस स्टेट' है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में आयोजित सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के लिए नवचयनित 371 लेखा परीक्षकों एवं स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लिए नवचयनित 129 लेखा परीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यह बातें कहीं। अपने संबोधन से पहले सीएम ने नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब हमने सरकार बनाई, खजाना खाली था। हमें अपने चुनावी वादों को निभाना था, लेकिन किसी भी बैंक का चेयरमैन या सीएमडी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं था। यानी, यूपी को कर्जा नहीं देना है। ऐसी छवि बना दी गई थी हमारे प्रदेश की। तब उस कठिन दौर में हमने तय किया कि बैंकों या वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहने के बजाय हम अपने संसाधन बढ़ाएंगे।

सहकारिता विभाग में 'स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार' अभियान का शुभारम्भ

'5S' पद्धति अपनाने से स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं कार्यकुशलता को मिलेगा बढ़ावा : शर्मा

4 से 29 मई तक तीन चरणों में संचालित होगा अभियान

जयपुर(नि.सं.)। सहकारिता विभाग में कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने, कार्यालयों को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाने तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 'स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार' विशेष अभियान का सोमवार से शुभारम्भ हुआ। यह अभियान प्रधान कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 4 से 29 मई 2026 तक चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा, जिसमें कार्यालयों की साफ-सफाई सहित चिह्नित रिकॉर्ड एवं कबाड़ के निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी। सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर नेहरू सहकार भवन में सभी अनुभागों एवं भवन में स्थित सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए कार्यस्थल की स्वच्छता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर जोर

दिया। डॉ. शर्मा ने कहा कि कार्यालयों में रिकॉर्ड के अव्यवस्थित प्रबंधन, अनुपयोगी सामग्री के संधारण एवं अस्वच्छता से राजकार्य प्रभावित होता है तथा आमजन में विभाग की नकारात्मक छवि बनती है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यालय साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहेगा तो न केवल कार्य करने का सकारात्मक माहौल बनेगा, बल्कि कार्यों के निष्पादन में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे वांछित रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध हो सकेगा साथ ही, स्वच्छता बनाए रखने से विभिन्न बीमारियों के खतरे को भी कम किया जा सकता है।

रिकॉर्ड प्रबंधन एवं निस्तारण पर विशेष जोर

शासन सचिव ने कबाड़ के निस्तारण, फाइलों, बस्तों एवं अलमारियों को सुव्यवस्थित रखने, टूटी कुर्सियों की मरम्मत, पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण, शौचालयों की नियमित सफाई तथा कार्यालयों की दीवारों पर रंग-रोगन जैसे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सिविल लाइंस तक प्रदर्शन विरोध

जयपुर में ट्रैफिक मार्शल के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

कहा- 4 महीने से वेतन नहीं मिला, अब बिना आदेश हटाया जा रहा, अटेंडेंस दर्ज नहीं हो रही

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू की गई ट्रैफिक मार्शल योजना अब विवादों में घिर गई है। मार्शल के रूप में कार्यरत युवाओं का आरोप है कि पिछले चार महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और अब बिना किसी आधिकारिक आदेश के उन्हें मौखिक रूप से ड्यूटी से हटाया जा रहा है। रामनिवास बाग से सिविल लाइंस तक प्रदर्शन विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में ट्रैफिक मार्शल पहले रामनिवास बाग में एकत्रित हुए और फिर अपनी समस्या लेकर सिविल लाइंस पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास को अपनी पीड़ा सुनाई।

मार्शल की अटेंडेंस जानबूझकर दर्ज नहीं की जा रही

बगरू निवासी हंसराज पिपरीवाल ने कहा- पूर्व ट्रैफिक डीसीपी सुमित महरड़ा द्वारा की गई नियुक्तियों को नए अधिकारी के आने के बाद बदला जा रहा है और बिना किसी लिखित आदेश के हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोल्याकावास, अलवर की किरण गुर्जर ने बताया- फरवरी में जॉइन किया था और यह नौकरी उनकी पढ़ाई व खर्च में सहायक थी, लेकिन अब तक उन्हें मेहनताना नहीं मिला। पूजा शर्मा ने कहा- मार्शल की अटेंडेंस जानबूझकर दर्ज नहीं की जा रही और ऑफिशियल ग्रुप भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जहां जयपुर में यह व्यवस्था कमजोर की जा रही है, वहीं जोधपुर में इसे शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया वे अलवर निवासी है और यहां एमए की पढ़ाई कर रही है।

न्यूज ब्रीफ

PWD का अधिशाषी अभियंता 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर/अलवर (वि.सं.)। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की अलवर चौकी (प्रथम) ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशाषी अभियंता (TA) को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे के नाम से लक्ष्मणगढ़ रोड (स्टेट हाईवे 44) स्थित ग्राम बरखेड़ा में HPCL कंपनी का पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एलओआई (LOI) जारी हुई थी। इस पेट्रोल पंप के लिए एनओसी (NOC) जारी करने के बदले पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तैनात अधिशाषी अभियंता कृष्ण अवतार गुप्ता 40,000 रुपये की रिश्वत मांगकर उसे लगातार परेशान कर रहा था।

कार-स्कूटी की टक्कर में 3 युवकों की मौत

2 लोग घायल, रेलिंग तोड़कर 40 फीट नीचे गिरीं गाड़ियां

उदयपुर(वि.सं.)। उदयपुर में इनोवा क्रिस्टा और स्कूटी के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। स्कूटी सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 लोग घायल हैं। दोनों गाड़ियां ब्रिज की रेलिंग तोड़ती हुई करीब 40 फीट नीचे जा गिरीं। हादसा प्रतापनगर थाना इलाके में रविवार देर रात हुआ। प्रतापनगर थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित ने कहा- टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। युवकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। प्रतापनगर थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित ने बताया कि स्कूटी सवार तीनों युवक कैटरिंग का काम करते थे। वे रविवार रात करीब 1:30 बजे एक शादी समारोह का काम निपटाकर प्रतापनगर से मादड़ी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एकलिंगपुरा चौराहा से प्रतापनगर की तरफ आ रही इनोवा कार से स्कूटी की टक्कर हो गई।

पुलिस ने 2 करोड़ तक के 790 मोबाइल बरामद किए: साइबर ठगी के 3.85 करोड़ रुपए होल्ड करवाएं

65.48 लाख रुपए पीड़ितों के खातों में वापस रिफंड

जयपुर(नि.सं.)। पुलिस ने साल 2026 गुमशुदा और चोरी हुए 790 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जयपुर ईस्ट पुलिस ने मोबाइल फोन की रिकवरी के लिए चलाए गए अभियान ÷ऑपरेशन री-कॉल÷ के तहत ये कार्रवाई की। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि केवल अप्रैल महीने में ही विशेष अभियान चलाकर अलग-अलग राज्यों से 400 मोबाइल फोन ट्रेस कर

बरामद किए गए। इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया गया, जिससे पीड़ितों के चेहरों पर खुशी लौट आई। शुरूआती दौर में जांच में सामने आया कि कुछ मोबाइल चोरी के थे, जबकि कुछ मोबाइल ऐसे थे जो गिर गए या कहीं छुट गए थे। डीसीपी ईस्ट ने ये भी बताया कि कई फोन में सेटिंग होती है कि फोन शटडाउन करने के लिए पासवर्ड डाला जाए, यदि यूजर ऐसा करता है तो चोरी जैसे मामलों में ऐसे मोबाइल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के खिलाफ भी जयपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। साइबर सेल ने अप्रैल तक करीब 3.85 करोड़ रुपए की ठगी राशि होल्ड करवाई गई, जिसमें से करीब 65.48 लाख रुपए पीड़ितों के खातों में वापस रिफंड कराए गए हैं।

अटलांटिक महासागर

समुद्र में जहाज पर चूहों वाला वायरस फैला:हंतावायरस से 3 लोगों की मौत

प्राया(एजेंसी)। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर चूहों वाले वायरल (हंतावायरस) संक्रमण का मामला सामने आया है। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है और कम से कम तीन लोग बीमार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इसकी पुष्टि की। MV होंडियस नाम के इस क्रूजशिप को फिलहाल अफ्रीकी देश केप वर्डे की राजधानी प्राया में रोका गया है। अभी यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं मिली है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि संक्रमण फैलने के खतरे को नियंत्रित किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य

संगठन (WHO) के अनुसार, जहाज पर 6 लोगों में संक्रमण जैसे लक्षण मिले हैं। इनमें से एक मामले की पुष्टि लैब में हो चुकी है। एक मरीज दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, जबकि दो को जहाज से निकालने की तैयारी की जा रही है। यह भी अभी पता नहीं है कि सभी बीमार लोग हंतावायरस से संक्रमित हैं या नहीं। यह बीमारी आखिर कैसे और कहां से फैली है, इसकी जांच चल रही है।

7 हफ्ते में कई देशों से गुजरा क्रूज

नीदरलैंड के झंडे वाला यह क्रूज शिप 20 मार्च को अर्जेंटीना के उशुआइया से रवाना हुआ था।

मुख्यमंत्री ने गलता तीर्थ के विकास को लेकर ली बैठक

गलता मार्गों पर हो धार्मिक चित्रण, प्रवेश द्वार पर लगाई जाए सभी मंदिरों की जानकारी : मुख्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गालव ऋषि की तपोस्थली गलता तीर्थ के प्रति आमजन में विशेष श्रद्धा का भाव है। ऐसे में तीर्थ के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए पौराणिकता एवंआधुनिकता केसंगमके साथ व्यवस्थाओं को विकसित किया जाए।

उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप जिला प्रशासन और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथकार्य करें।उन्होंने वृद्धजनों के लिए ट्रैवलेटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने जयपुर में गलता धाम परिसर में तीर्थ के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने तीर्थ परिसर में बने मंदिरों एवं पवित्र कुंडों की दीवारों के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलता धाम आने वाले दोनों रास्तों के विकास सहित आमजन के लिए समुचित वाहन पार्किंग विकसित की जाए। साथ ही, गलता मार्गों पर धार्मिक चित्रण किया जाए, ताकि प्रवेश से लेकर तीर्थ तक आने वाले श्रद्धालुओं का मन आस्था से भर उठे। उन्होंने प्रवेश द्वार पर गलता तीर्थ में बने मंदिरों की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने की पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री ने सीताराम जी मंदिर में सपत्नीक पूजा-अर्चना कर आरती उतारी और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने गलता परिसर में बने विभिन्न मंदिरों का अवलोकन भी किया। इसके बाद उन्होंने गलता तीर्थ के पवित्र कुंड में अर्घ्य भी दिया।

सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसजेंडर संशोधन एक्ट पर केंद्र-राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह संशोधन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन (अपनी पहचान खुद तय करने) का अधिकार छीनता है।

केरल जनादेश मतदाताओं के बदलते मिजाज को दर्शाता है: केसी वेणुगोपाल

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल चुनाव परिणामों को जनभावना में निर्णायक बदलाव बताया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि ये परिणाम केरल भर में परिवर्तन समर्थक लहर के विपक्ष के आकलन को सही साबित करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 102 सीटों पर आगे चल रहा है, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा 36 सीटों पर, और भाजपा ने नीमोम सहित दो सीटें जीती हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, हम यही कहते रहे कि एक लहर बन रही है। यहां तक कि जब एग्जिट पोल ने इसके विपरीत संकेत दिए, तब भी हमें मजबूत जीत का भरोसा था और हम 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की उम्मीद कर रहे थे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी पहुंचीं गलताजी, वीडियो बनाएः बोलीं- जयपुर के लिए अलग से समय लेकर आती हूं

जयपुर (नि.सं.)। जयपुर इन दिनों बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। एक ओर हिंदी सिनेमा की चर्चित अदाकारा मंदाकिनी जयपुर की विरासत और आध्यात्मिक स्थलों की खूबसूरती में खोई नजर आईं। वहीं, सोमवार को बॉलीवुड सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण भी जयपुर पहुंचे। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री मंदाकिनी पिछले कुछ दिनों से जयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे शहर की हेरिटेज लोकेशंस, ऐतिहासिक धरोहरों और आध्यात्मिक स्थलों का आनंद लेती नजर आ रही हैं। वे गलताजी मंदिर भी पहुंचीं। यहां उन्होंने दर्शन किए और मंदिर परिसर की खूबसूरती को करीब से देखा। गलताजी मंदिर में मंदाकिनी ने न केवल पूजा-अर्चना की, बल्कि वहां मौजूद प्राचीन धरोहरों, कुंडों और स्थापत्य शैली के बीच वीडियो शूट भी करती नजर आईं। मंदिर परिसर और आसपास की ऐतिहासिक इमारतों के साथ उन्होंने कई वीडियो और विजुअल्स रिकॉर्ड किए।

मंदाकिनी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जयपुर आना उनके लिए हमेशा से खास रहा है। इस शहर की हर इमारत, हर गलियारा और हर हेरिटेज स्ट्रक्चर अपने भीतर एक अलग कहानी समेटे हुए है। जयपुर की वास्तुकला, शाही अंदाज और सांस्कृतिक गरिमा हमेशा आकर्षित करती है। जब भी वे जयपुर आती हैं, पूरा समय लेकर आती हैं, ताकि इस शहर की खूबसूरती को करीब, सुकून और गहराई से महसूस कर सकें।

विशेष निरोधात्मक अभियान **प्रदेश में अवैध मदिरा पर प्रभावी कार्रवाई जारी**

22410 लीटर वॉश नष्ट, 73 अभियोग दर्ज, 12 गिरफ्तार

जयपुर(नि.सं.)। आबकारी आयुक्त श्री नमित मेहता के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए जारी विशेष निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदिरा जब्त करते हुए हजारों लीटर वॉश नंष्ट कर अभियोग दर्ज किए गये है। जिला जालोर में ईपीएफ की बड़गांव से बापला रोड़ पर नाकाबंदी के दौरान एक मारूति कार की जांच करने पर अन्य राज्य में बिक्री योग्य अवैध मदिरा के 24 कार्टन व देसी मदिरा के 14 कार्टन सहित कुल 38 कार्टन जब्त कर अभियोग दर्ज किया। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही व

अनुसंधान जारी है। भीलवाड़ा में अवैध शराब के विरूद्ध आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई में 2 अभियोग दर्ज किए गए। श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर क्षेत्र में दबिश देते हुए 400 लीटर वॉश एवं 2 पुरानी भट्टियां नष्ट की गई। इसी क्रम में श्रीगंगानगर के पड़त मदिरा क्षेत्र में कार्रवाई कर एक कार्टन में 28 पव्वे जीएसएम बरामद किया। सूरतगढ पड़त मदिरा दुकान भोजेवाला क्षेत्र में दो कार्टन में 78 पव्वा जीएसएम बरामद किया। इसी क्षेत्र के ग्राम मानेवाल, सादक वाला एवं फरीदसर में दबिश देकर 300 लीटर वॉश एवं 2 कच्ची भट्टियां भी नष्ट की गई। इसी प्रकार हनुमानगढ़ के मक्कासर और अमरपुरा क्षेत्र में दबिश की कार्रवाई कर 2400 लीटर वॉश सहित 6 कच्ची भट्टियां नष्ट कर 2 अभियोग दर्ज किए गए। अलवर जिले के आबकारी थाना क्षेत्र रामगढ़ व राजगढ़ में ईपीएफ दल ने दबिश देकर करीब 2 हजार लीटर वॉश एवं 2 भट्टियां नष्ट की। मौके पर 2 अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। भरतपुर के आबकारी थाना क्षेत्र डीग के सीकरी पहाड़ी, गोपालगढ, कामां एवं सतवाड़ी में दबिश देते हुए 182 पव्वे विभिन्न ब्रांड एवं 107 बीयर विभिन्न ब्रांड की जब्त की गई। मौके से अभियुक्त फरार हो गया। अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही जारी है। आबकारी थाना क्षेत्र खेरवाड़ा में ईपीएफ दल ने 1500 लीटर महुआ वॉश नष्ट करते हुए मौके से 50 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की। अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। मेड़ता सिटी में ईपीएफ दल ने दबिश देकर 500 लीटर वॉश नष्ट किया साथ ही 12 लीटर अवैध हथकड़ शराब

'पधारो म्हारे देस'; हाईटेक टूरिज्म का मॉडल बना राजस्थान

एक ही दिन में 1 लाख पर्यटकों की टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड

निखर रहा हमारा पर्यटन, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम से मिल रही अलग दिशा

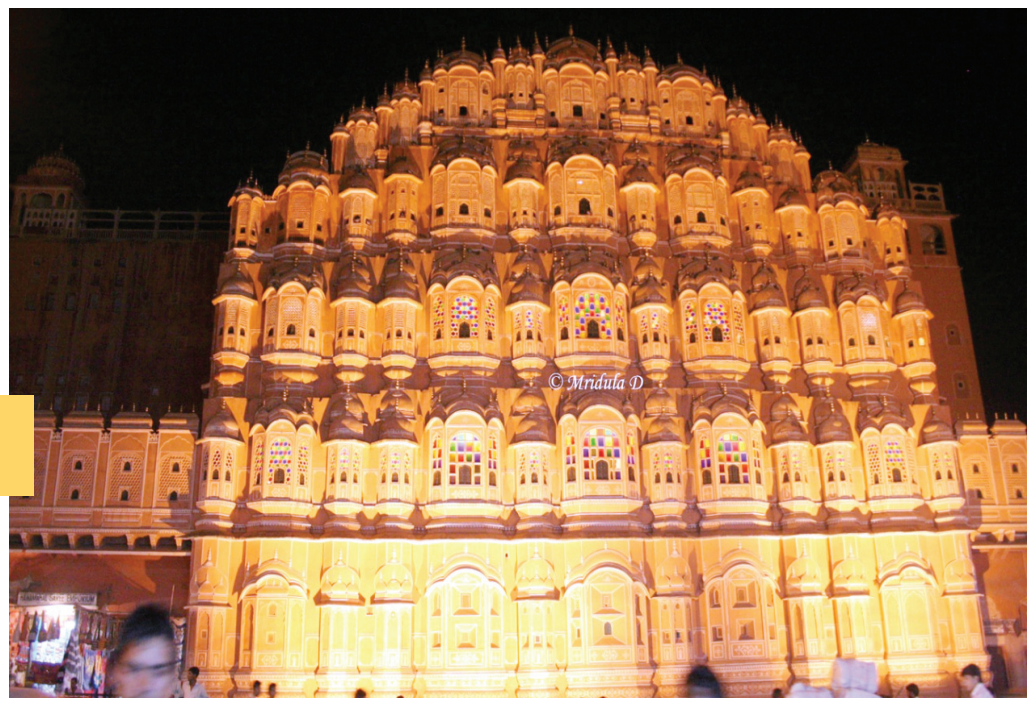

लोक टुडे। जयपुर

अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और भौगोलिक विविधता के लिए मशहूर राजस्थान अब डिजिटल प्रगति में भी मॉडल प्रदेश बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल, दूरदर्शी एवं प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान सरकार ई-गवर्नेंस के साथ डिजिटल नवाचारों को भी बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (ओबीएमएस) देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी-साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग अपनी छुट्टियां राजस्थान में बिताने को प्राथमिकता देते हैं। इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए एकीकृत डिजिटल पोर्टल तथा ओबीएमएस मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए। जिनके माध्यम से प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थलों, स्मारकों, संग्रहालयों, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोलॉजिकल पार्कों, उद्यानों, सफारी, बोटिंग, कैफेटेरिया, होटल्स आदि की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा रही है।

एक दिन में एक लाख तक बुकिंग, सफलता को मिला सम्मान :

ओबीएमएस को देशी-विदेशी पर्यटकों का भी भरपूर रेस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि एक दिन में सर्वाधिक लगभग 1 लाख पर्यटकों की टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड 28 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया। अब तक के आंकड़ों की बात करें, तो लगभग 90 लाख बुकिंग्स के जरिए 3 करोड़ से अधिक पर्यटकों को सेवा प्रदान की जा चुकी है। इनमें 70 से अधिक देशों के विदेशी पर्यटक शामिल हैं। वहीं, पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों को 30 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी सफलता को देखते हुए ओबीएमएस को वर्ष 2025 में स्कॉच अवॉर्ड में सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

100 से ज्यादा पर्यटन स्थल जुड़े, बढ़ाया जा रहा दायरा :

एक क्लिक पर पूरे राजस्थान की जानकारी और टिकटिंग उपलब्ध करवाने के लिए अब तक 100 से अधिक पर्यटन स्थलों को पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। जिनमें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आमेर किला, जंतर-मंतर, हवा महल, राजकीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल इत्यादि (47 स्थल), वन विभाग के सरिस्का टाइगर सफारी, झालाना लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इत्यादि (21 स्थल), राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चित्तौड़गढ़ एवं कुम्भलगढ़ किला लाइट एंड साउंड शो, दुर्ग कैफेटेरिया पड़ाव नाहरगढ़, होटल लेक पैलेस सिलीसेढ़ (4 स्थल), जयपुर विकास प्राधिकरण के किशन बाग, मसाला चौक, सावन भादो बाग (3 स्थल), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चित्तौड़गढ़ किला, कुम्भलगढ़ किला, भानगढ़ किला, डीग भवन इत्यादि (7 स्थल), जवाहर कला केन्द्र (15 स्थल) तथा जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी भी शामिल हैं। राज्य सरकार की इस अभिनव पहल से पर्यटन सेवाओं में पारदर्शिता आने के साथ ही मैनुअल कार्यों में भारी कमी हुई है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। इसी क्रम में राज्य सरकार ओबीएमएस को और अधिक विस्तार देने जा रही है। अब जल्द ही आरटीडीसी के होटलों की ऑनलाइन बुकिंग और जवाहर कला केन्द्र के कार्यक्रमों की टिकट बुकिंग भी इस प्लेटफॉर्म पर शुरू की जाएगी। साथ ही, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लगभग 150 से अधिक राजस्थान से बाहर के पर्यटन स्थलों को भी ओ.बी.एम.एस. पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है तथा बुकिंग करने की सुविधा प्रक्रियाधीन है।

पर्यटकों के लिए वन स्टॉप सेंटर

क्यूआर-आधारित ई-टिकट बुकिंग एवं वैलिडेशन प्रणाली पूरी तरह कैशलेस एवं पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा देती है। इस पर 'राजस्थान पैकेज' एवं 'जयपुर पैकेज' सहित कम्पोजिट एवं सिटी-आधारित पैकेज भी उपलब्ध हैं। वहीं, पर्यटन स्थलों पर क्यूआर-आधारित ऑडियो गाइड, डिजिटल बोर्डिंग पास, एडवांस चेक-इन, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के साथ ही कैंसलेशन एवं आसान रिफंड जैसे फीचर उपयोगकर्ता के अनुभव को काफी बेहतर करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट सर्च, इंटरएक्टिव मैप, एनालिटिक्स एवं रियल-टाइम डैशबोर्ड जैसे फीचर्स से पर्यटकों को एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल जाती है। फीडबैक सिस्टम का भी ध्यान रखते हुए ऑनलाइन शिकायत एवं निवारण और आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। OBMS APP एवं पोर्टल राजस्थान सरकार की एक परिवर्तनकारी डिजिटल पहल साबित हो रहा है, जिससे पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, वहीं रोजगार सृजन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से राजस्थान सुशासन और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनता जा रहा है।

एसआई भर्ती-2021 भर्ती रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

लोक टुडे। जयपुर

सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 मामले में चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बता दें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले इस भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे बाद में खंडपीठ ने भी बरकरार रखा। खंडपीठ के इसी फैसले को अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है।

सरकार ने अभी तक नहीं की अपील :

दरअसल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपील नहीं की है। जबकि ट्रेनी स्टॉफ लगातार सरकार से मांग कर रहे है कि वह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करके मजबूत पैरवी करें। सरकार ने एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ खंडपीठ ने भी देरी माफी के साथ अपील फाइल की थी। बता दें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे खंडपीठ ने 4 अप्रेल 2026 को फैसला सुनाते हुए बरकरार रखा था।

सैटेलाईट अस्पताल में लगेगी सोनोग्राफी मशीन, शुरू होगा लेबर रूम

लोक टुडे। अजमेर

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर जिले में अस्थाई भवन में संचालित कोटड़ा सैटेलाइट चिकित्सालय का निरीक्षण कर वहां संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अस्थाई भवन में संचालित कोटड़ा सैटेलाइट चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन संचालित करने और लेबर रूम तैयार करने के निर्देश दिए है ताकि यहां गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सुविधा विकसित की जा सके। इसी तरह अस्पताल में निःशुल्क दवा-जांच एवं उपचार के लिए भी अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आयुष क्लिनिक में भी चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित होगी। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए है कि गर्मी को देखते हुए चिकित्सालयों में मौसमी बीमारियों की संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार, दवा उपलब्धता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया तथा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। साथ ही मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओपीडी पंजीकरण काउंटर को चिकित्सालय परिसर के भीतर छायादार स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश प्रदान किए। देवनानी ने एनसीडी सहित विभिन्न इकाइयों में कार्मिकों की उपलब्धता एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, शिशु रोग, प्रयोगशाला एवं पैथोलॉजी सेवाओं की स्थिति का अवलोकन करते हुए सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा साफ-सफाई, मरीजों की देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने को निर्देशित किया। ऑपरेशन थिएटर का भी अवलोकन करते हुए वहां उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं की जानकारी चिकित्सकों से ली और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने चिकित्सकों को समय पर उपस्थित रहने, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराने तथा संवेदनशीलता के साथ सेवाएं देने के निर्देश दिए।

सीएम की ओड समाज को सौगात, मुख्यमंत्री आवास में ओड समाज संवाद कार्यक्रम आयोजित

जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की

लोक टुडे। जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ओड समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है तथा इसने राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान दिया है। श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान इसकी पहचान हैं। उन्होंने कहा कि इस समाज ने किलों और महलों के निर्माण में अपनी कुशलता दिखाई है तथा जल संरचनाओं के निर्माण की इनमें अद्भुत कला है। मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ओड समाज संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा को समृद्ध बनाने में ओड समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस समाज के पूर्वजों ने पानी के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना सिखाया। उन्होंने कार्यक्रम में ओड समाज को बड़ी सौगात देते हुए रामदेवरा में धर्मशाला एवं जयपुर में छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पाक विस्थापित ओड समाज के लोगों की हर संभव सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं को धरातल पर उतार रही है। वहीं, किसानों को दिन में बिजली दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के लिए जनधन खाता, रसोई गैस सिलेण्डर, हर घर नल से जल, शौचालय निर्माण और लखपति दीदी जैसी अनेक योजनाएं चलाई हैं। किसानों को सम्मान निधि तथा जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा एवं मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 'श्रमेव जयते' का आह्वान कर'श्रमिकों का कल्याण राष्ट्र निर्माण की नींव'का स्पष्ट संदेश दिया है तथावे श्रमिक-सशक्तीकरण पर जोर दे रहे हैं। श्रमिकों का सम्मान, सहूलियत और सुरक्षा श्रम नीति का आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मान-धन जैसी पेंशन योजना शुरू कर असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सहारा दिया है। इसमें 27 हजार से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। उन्होंने चार नई श्रम संहिताएं लागू कर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्यस्थल की सुनिश्चितता की है।

20 लाख श्रमिकों का पोर्टल पर पंजीयन :

उन्होंने कहा किलगभग 20 लाख श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। वहीं, इनके कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए श्रम-सेतु मोबाइल ऐप शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की है। शहरी क्षेत्र में घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू समुदाय के लोगों को करीब डेढ़ हजार पट्टे जारी किए हैं। इन समुदायों के उत्थान के लिए दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदाय और मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों को हर जिले में शिक्षा के लिए एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 80 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

53 हजार से अधिक लाभार्थियों को बांटा ऋण :

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ऋण पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान के आदेश जारी किए हैं। अब तक 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा 53 हजार से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

विभिन्न योजनाओं में 980 करोड़ का भुगतान :

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 26 रुपये की वृद्धि की है। विभिन्न योजनाओं में करीब 9 लाख श्रमिकों को 980 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

कॉलेजों में राजकीय निधि कोष में लिए जाने वाला शुल्क माफ :

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 2 हजार किसानों को महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना के तहत मंडी श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई है। लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क भी माफ किया है। उन्होंने ओड समाज के युवाओं से आधुनिक कौशल प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्रदाता बनने, बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने तथा महिलाओं को आगे बढ़ाने और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इस अवसर पर ओड महासभा के अध्यक्ष प्रेम ओड एवं अन्य पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ओड समाज के लोग उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रिक, प्रकाशन, संपादक - नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर - 302006 से मुद्रिक एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झेलना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) प्रकाशित प्रबंध संपादक - पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)